जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 26 संख्याः 213 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 4 मार्च, 2022 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

प्रदेश में हुई राजनैतिक नियुक्तियों के लिए धन्यवाद देने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, यहां तक कि पुलिस को बैरिकेडिंग भी करनी पड़ी।

पायलट के निवास पर धन्यवाद जताने के लिये भीड़ उमड़ी

- इनमें प्रमुख थे, गजराज खटाना, सुरेश मोदी, अभिमन्यु पूनिया, सुचित्रा आर्य, करण सिंह, उचियारड़ा व हरीश यादव।

जयपुर, 3 मार्च (का.प्र.)। सचिन पायलट के निवास पर गुरुवार को समर्थकों की भीड़ के चलते पुलिस को बैरिकेडिंग कर रास्ते रोकने पड़े।

सचिन पायलट कोटे से मिली राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नेता उनका धन्यवाद और आभार जताने अपने समर्थकों के साथ उनके निवास पर पहुंचे। इस दौरान गजराज खटाना, सुरेश मोदी, अभिमन्यु पूनिया, सुचित्रा आर्य, करण सिंह उचियारड़ा और हरीश यादव अपने समर्थकों के साथ उनके आवास पर पहुंचे।

सुचित्रा आर्य को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमैंट बोर्ड उपाध्यक्ष बनाये जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सिविल लाइन्स स्थित सरकारी आवास पहुंचे और आभार जताने के साथ ही उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा "कि वे कांग्रेस हाईकमान व पायलट साहब के आभारी हैं जिन्होंने किसान नेता सुचित्रा आर्य को राजस्थान सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर प्रदेशभर के किसान वर्ग की जनभावनाओं का सम्मान किया। यह कदम कांग्रेस पार्टी व कमेरे वर्ग में आशा एवं उत्साह का संचार करेगा। इस अवसर पर आर्य ने अपने समर्थकों सहित पायलट का आभार जताते हुए कहा कि राहुल गांधी की किसानों की आय बढ़ाने की सोच को लेकर उनका मानना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आदित्यनाथ तो भोगी हैं, मैं हूँ असली योगी'

ममता बनर्जी ने वाराणसी में आयोजित सपा की चुनाव अभियान की आमसभा में "हर, हर, महादेव" का उद्घोष किया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मार्च। एक विडम्बनापूर्ण मोड़ लेते हुये, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के साथ अपना चुनावी मंच साझा किया। इसे विपक्षी एकता का प्रदर्शन माना जाये या फिर यह वोटों के लिये अखिलेश यादव का अंतिम क्षणों में लिया जाने वाला सहारा है।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आज वारावणी की एक जनसभा में, सपा के एक बहुत बड़े चुनावी "शो" में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

पवित्र नगर वाराणसी में ममता ने यू.पी. में मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की और स्वयं को उनसे बड़ा योगी बताया। उन्होंने आदित्यनाथ को "योगी" के ठीक विपरीत एक "भोगी" बताया। फिर उन्होंने भगवान शिव की इस नगरी में अपनी आध्यात्मिकता का बखान करते हुये "हर-हर महादेव" से वातावरण गुंजायमान कर दिया।

ममता बनर्जी, ममता बनर्जी ही हैं। वे जहाँ भी होती हैं, वे स्वयं को हर तरह से सर्वश्रेष्ठ दिखाती हैं। पिछले सप्ताह, जब बेहद लोकप्रिय बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी का निधन हुआ था तो ममता ने जोर देते हुये कहा था कि स्वर्गीय संध्या मुखर्जी ममता के लिखे गीतों को बहुत पसंद करती थीं तथा उन्होंने उनके लिये गीत गाये थे।

- पर, ममता बनर्जी को सपा के मंच पर इतना महत्व देना विपक्ष की एकता का प्रतीक माना जाये या अखिलेश का वोट बटोरने का हताश भरा प्रयास।
- अखिलेश, अपनी विशालहृदयता इस लिये भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ममता की पार्टी यू.पी. में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही।
- परन्तु ममता के राज्य, प. बंगाल में थोड़ी सी अटपटी स्थिति बन रही है। एक मुस्लिम युवक की छत से गिरने से मृत्यु हो गयी और मुस्लिम संगठन इस दुर्घटना की बंगाल की पुलिस से नहीं, बल्कि किसी अन्य पुलिस संगठन से जांच की मांग कर रहे हैं।

वस्तुतः, उत्तर प्रदेश के चुनावों से ममता बनर्जी का प्रत्यक्ष लेना-देना नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी वहाँ चुनाव मैदान में नहीं है। इसलिये, उनकी अखिलेश से किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है। वे तो एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य के चुनाव में सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आई थीं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को 2024 के संसदीय जनादेश की पूर्व सूचना माना जा रहा है।

दरअसल, उन्होंने आज वाराणसी के अपने चुनावी उद्बोधन में काफी कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम कुछ भी क्यों न रहें, वे तो पश्चिम बंगाल के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के हर संभव प्रयास कर रही हैं। लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर बार-बार प्रश्न चिन्ह लगते आ रहे हैं।

कांग्रेस सभी राज्यों के चुनावों में, ममता बनर्जी को पूरी तरह दूर रख रही है तथा ममता विभिन्न राज्यों में कांग्रेसजनों को छीनकर, राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं। गोवा में उन्होंने कांग्रेस नेताओं को ठीक उसकी तरह तोड़कर अपनी पार्टी में लिया था, जैसा उन्होंने मेघालय में किया था।

राहुल गांधी के खिलाफ उनकी बार-बार की जाने वाली तीखी टिप्पणियों से यह तो सुनिश्चित हो गया है कि एकीकृत विपक्ष में उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। वस्तुतः ऐसा भी माना जा रहा है कि वे भाजपा की मदद करने के लिये, एकीकृत विपक्षी मोर्चे को तितर-बितर करने की कोशिश कर रही हैं।

जैसी कि उनकी आदत है, उनका तौर तरीकों में साम्प्रदायिकता का पुट था। उत्तर प्रदेश की वाराणसी नगरी में उन्होंने "हर हर महादेव" उच्चारित किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गंगा नदी के किनारे कई आध्यात्मिक अनुभव हुये हैं।

लेकिन उनके अपने राज्य में सब-कुछ ठीक-ठाक नहीं है। एक मुस्लिम युवा की मृत्यु, जो टी.एम.सी. की सहअपराधिकता का संदेह पैदा कर रही है, के कारण, उन्हें मुस्लिमों के प्रहारों का सामना करना पड़ रहा है।

कलकत्ता के पास आमटा में, एक युवक को उसके मकान की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया था। इसके बाद, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो अनेक इस्लामिक संगठनों का विशिट मुखपत्र हैं, ने इस युवक की मृत्यु की निष्पक्ष जाँच के लिये अभियान छेड़ रखा है। फ्रन्ट की माँग है कि इसकी जाँच राज्य पुलिस से नहीं, बल्कि किसी अनय एजेंसी से कराई जाये।

राज्य भाजपा ने इस युवक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था।

सुप्रीम कोर्ट के जजों की गुहार!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3मार्च। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद भवन के बिल्कुल नजदीक स्थित अपने बँगलों में बंदरों के उत्पात से इतने भयभीत हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने निविदा जारी करके हाउस कीपिंग एजेंसियाँ आमंत्रित की हैं ताकि वे "मंकी स्केअरर्स" की सेवाएं उपलब्ध कराके उन्हें सुरक्षा एवं राहत दे सकें।

- अपने बंगलों में घूमते बंदरों के झुण्डों से घबरा कर जजों ने निविदा आमंत्रित की, बंदरों को डराने व भगाने वालों के लिये।

निविदा सूचना में कहा गया है कि बंदर भगाने वाले इन लोगों को जब और जैसी जरूरत के मुताबिक शुरू में 6 माह के लिए तैनात किया जायेगा। ये लोग सर्वोच्च न्यायालय से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 35-40 बँगलों पर तैनात किये जायेंगे।

बंदरों के संकट का सामना उस क्षेत्र में रहने वाले मंत्री तथा सांसद तथा सरकारी स्टाफ के लोग भी कर रहे हैं। बंदर सचिवालय तथा अन्य सरकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

2 जी स्कैम

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मार्च। एस्सार ग्रुप के लूप टेलीकॉम और ट्रेडिंग लिमिटेड की ओर से "एंट्री फीस" को लेकर दायर एक अपील को सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को खारिज कर दिया। अपील में कहा गया था कि वर्ष 2007 में उन्होंने 21

- सुप्रीम कोर्ट ने स्कैम में लिप्त पार्टियों की "एन्ट्री फीस" वापस करने से इंकार किया।

सर्विस क्षेत्रों में 2 जी मोबाइल फोन लायलैंस के लिए 1454.94 करोड़ रूपए एंट्री फीस के रूप में जमा कराए थे, लेकिन उन्हें प्रदत्त सभी लायसैंसों को सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2012 के एक निर्णय में रद्द कर दिया गया, जिसे देखते हुए उन्हें उक्त एंट्री फीस रिफण्ड की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान के जादूगर की जादूगरी, अपने ही उपमुख्यमंत्री को गायब कर दिया: डॉ. सतीश पूनिया

रीट पेपर लीक मामले में सी.बी.आई. जांच की मांग भी पूनिया ने दोहराई

- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आमेर आने वाला हर पर्यटक पूछता है कि, नाथी का बाड़ा कहां है, हमें वह देखना है।
- पूनिया के अनुसार, कांग्रेस सरकार को कर्जा लेकर घी पीने की आदत पड़ चुकी है।

जयपुर, 3 मार्च (वि.सं.)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने विधानसभा में बजट अभिभाषण पर बहस में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जादू करते-करते राजस्थान सरकार ने अपने ही उपमुख्यमंत्री को गायब कर दिया। इस दौरान पूनिया ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लेकर मौजूदा बजट की खामियों को गिनाया और साथ ही रीट पेपर लीक मामले में एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग की।

पूनिया ने कहा कि "महिला उत्पीड़न, बढ़ते क्राइम के बाद अब आत्मदाह के मामले में भी राजस्थान नंबर वन हो गया है। बजट में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना जिसके तहत साल 2024 तक राजस्थान के 86 लाख लोगों तक पानी पहुंचाना था, उसकी गति का जिक्र नहीं किया।

आज राजस्थान सरकार के चलते इस योजना की गति बेहद धीमी है। साल 2024 तक महज 60 लाख लोगों तक यह पानी पहुंच पाएगा।"

उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार कर्जा लेकर बजट पेश कर रही है। यह निर्भरता कम करने वाला नहीं निर्भरता बढ़ाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि अभी तीन साल में राजस्थान सरकार ने डेढ़ लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जो इस वर्ष दो लाख करोड़ को पार कर गया।

पूनिया के अनुसार कांग्रेस सरकार को कर्जा लेकर घी पीने की आदत पड़ चुकी है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में 60 लाख किसान हैं, जिनपर 1 लाख 20 हजार करोड़ का कर्जा है, जिसे गहलोत सरकार माफ करे।

पूनिया ने कहा कि राजस्थान में देश का हर तीसरा पर्यटक घूमने आता है और उनकी विधानसभा क्षेत्र आमेर में भी जो पर्यटक आता है, वो पूछता है "नाथी का बाड़ा कहां हैं, हमें वह देखना है।

सरकार ने बजट में आमेर विधानसभा को कुछ नहीं दिया, एकमात्र उपहार जो आईफोन दिया था, वह भी मैंने लौटा दिया।

सरकार को यदि डर नहीं है, तो वह रीट परीक्षा की अनियमितता की सीबीआई जांच करवाने से बच क्यों रही है।

फिटनेस सर्टिफिकेट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मार्च। सरकार ने प्रस्तावित किया है कि वाहन पर उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ ही, मान्य

- अब यह अनिवार्य होगा कि, सभी वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट इस तरह चिपका हो, जिससे साफ पढ़ा जा सके कि, सर्टिफिकेट कब तक वैध है।

फिटनैस सर्टिफिकेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। नीले बैकग्राउन्ड पर पीले रंग के बोल्ड अक्षरों वाला यह प्रमाण पत्र विन्ड स्क्रीन के ऊपरी हिस्से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं पुतिन को आदेश दूं युद्ध बन्द करने के लिये?'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 मार्च। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने गुरुवार को उस पी.आई.एल., जिसमें युद्ध-पीड़ित यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को निकाले जाने का अनुरोध किया गया था, पर खीजते हुये कहा कि कोर्ट रूस और

- सुप्रीम कोर्ट के मु.न्यायाधीश रमन्ना ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिये दर्ज याचिका की सुनवाई के दौरान झुंझला कर कहा।

यूक्रेन में चल रहे युद्ध के मामले में कुछ नहीं कर सकता।

जब यह पी.आई.एल. उनकी बैंच के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिये रखी गई तो उन्होंने कहा, "क्या मैं रूस के राष्ट्रपति को युद्ध रोकने के निर्देश दे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेंशन का टेंशन बताया राज्य बजट को पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि ने

महर्षि केन्द्र में वित्त सचिव और सी.ए.जी. के भी प्रमुख रहे हैं और कई बार राज्य का वार्षिक बजट बनाने का अनुभव है

-प्रकाश भण्डारी-

जयपुर, 3 मार्च। अशोक गहलोत सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2022-2023 के राज्य बजट, जिसे राज्य के पहले कृषि बजट का नाम और रूप भी दिया गया था, का सबसे चौंकाने वाला पक्ष राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित करने का निर्णय था और 23 हजार 488 करोड़ 56 लाख रूपए के घाटे के इस बजट के बाद, न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) का पल्ला झाड़कर पुरानी डिफाइन्ड पेंशन बेनेफिट स्कीम (डी.पी.बी.एस.) को अपनाकर, कर्ज में दबी राज्य सरकार ने अपने उपर कर्ज के बोझ को और अधिक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

पुरानी पेंशन स्कीम को अपनाने से राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई और कर्मचारी वर्ग राज्य सरकार को इस निर्णय के लिए धन्यवाद दे रहा है। अर्थशास्त्री राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए गए इस मंहगे उपहार की आलोचना कर रहे हैं और उनका यह मानना है कि यह योजना युवाओं की जेब खाली कर बुजुर्गों की जेबें भरने की है।

पेंशन के इस टेंशन का आकलन और विश्लेषण पद्म भूषण राजीव महर्षि ने किया है। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रहे महर्षि, जिन्होंने राज्य के वित्त सचिव के अलावा आगे चलकर केन्द्र सरकार में वित्त सचिव के अलावा गृह सचिव और भारत के नियंत्रक और महालेखाकार जैसे महत्वपूर्ण पदों को संभाला है, ने गहलोत सरकार के इस निर्णय की कटु आलोचना की है। राजीव महर्षि ने नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेन्स एण्ड पॉलिसी (एन.आइ.पी.एल.पी.) की एसोसिएट प्रोफेसर रेणुका साने के साथ गहलोत सरकार के इस लोक लुभावन उपहार का विश्लेषण किया है। उनका यह विचारोत्तेजक लेख का सार प्रस्तुत है:

- पुराने पेंशनर और फैमिली पेंशनरों की संख्या 5.6 लाख
- प्रतिवर्ष ऐसे पेंशनरों की संख्या में 30,000 की वृद्धि
- वर्तमान एन.पी.एस. पेंशनरों की संख्या 5.5 लाख
- पेंशन भुगतान पर प्रतिवर्ष भार 23,000 करोड़
- पेंशन भुगतान पर प्रतिवर्ष वृद्धि 7.5 प्रतिशत वर्ष 2030 तक
- राज्य का वर्तमान घाटा 29,400 करोड़
- वर्ष 2035 तक राज्य सरकार के पास पेंशन भुगतान के लिए धनराशि नहीं रहेगी

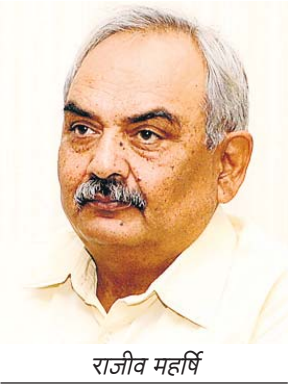

राजीव महर्षि

पेंशन का टेंशन विश्वव्यापी है। डिफाइन्ड पेंशन बेनेफिट स्कीम (डी.पी.बी.एस.) एक ऐसा रोग है जिससे भारत सहित विश्वभर के सभी समृद्ध देश ग्रस्त है। पेंशन देने के लिए या पेंशन योजना को पोषित करना एक ऐसी चुनौती बन गया है कि इसका समाधान ही नहीं निकल रहा है। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था, बेहतर खान-पान और अधिक जीने की चाह से अवकाश प्राप्त संवर्ग की जीवित रहने की दर पूर्व के मुकाबले काफी बढ़ गई है। अब लंबी उम्र तक लोग जीवित रहने लगे हैं। नतीजा यह हुआ कि जवान लोगों को अब वृद्धों की पेंशन के लिए अपनी जेबें हल्की करनी पड़ रही है। यह सब पूर्ति टैक्स के मार्फत हो रही है।

वर्ष 2003 से पूर्व सेवा में आने वाले कर्मचारियों को डी.पी.बी.एस. के अंतर्गत पेंशन देने का दायित्व केन्द्र और राज्य सरकारों पर है और सेना के जवानों और अधिकारियों को भी इस स्कीम के तहत ही पेंशन भुगतान होता है। लेकिन पेंशन का भुगतान बुजुर्गों के लिए युवा वर्ग टैक्स के जरिए करता है। आज के युवा वर्ग के अलावा कल जन्मने वाली संतानों को भी यह भुगतान भरने का दायित्व बना रहेगा।

वर्ष 2004 में केन्द्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना से पेंशन स्कीम चालू की। पश्चिम बंगाल सरकार के अलावा देश के सभी राज्यों ने इस स्कीम को अपनाया। इस स्कीम के अंतर्गत पेंशन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)